नईदुनिया

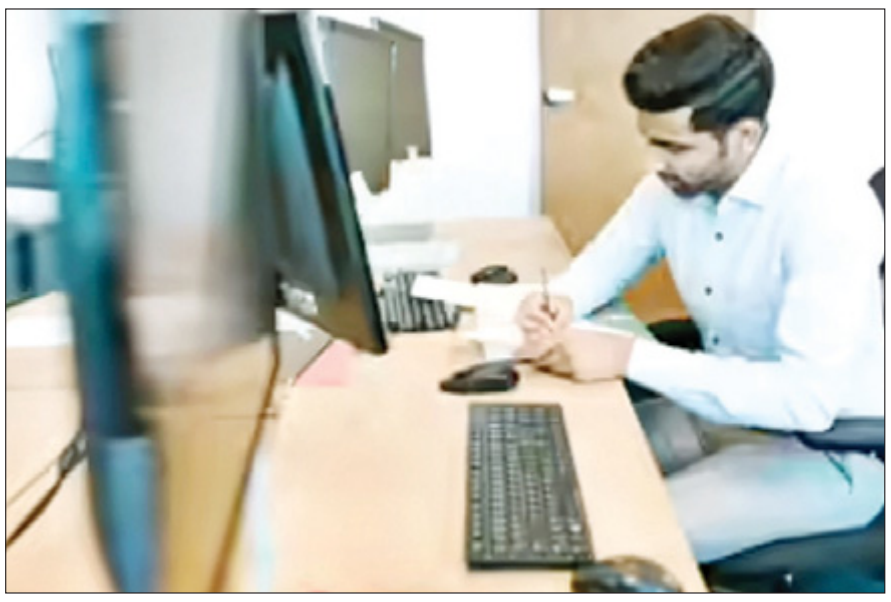

अमेरिका के रिटेल सेक्टर से भारतीय आईटी कंपनियों को राहत, पर खतरा बरकरार

एआई के बढ़ते इस्तेमाल से पारंपरिक आईटी सेवाओं की मांग पर बढ़ सकता है दबाव

नई दिल्ली

अमेरिका की बड़ी रिटेल कंपनियों का कारोबार सुधर रहा है और तकनीक पर खर्च भी बढ़ रहा है। इससे भारतीय आईटी कंपनियों को नए प्रोजेक्ट मिलने की उम्मीद बढ़ी है। हालांकि, तस्वीर पूरी तरह सकारात्मक नहीं है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के बढ़ते इस्तेमाल से पारंपरिक आईटी सेवाओं की मांग पर दबाव भी बढ़ सकता है। अमेरिका में उपभोक्ताओं का खर्च मजबूत बना हुआ है। लोग अभी भी खरीदारी कर रहे हैं, खासकर आनलाइन और कम कीमत वाले उत्पादों पर। इसी वजह से कई बड़ी रिटेल कंपनियों की बिक्री और मुनाफे में सुधार देखने को मिला है। अधिकांश कंपनियों ने पूरे साल के लिए अपने अनुमान बरकरार रखे हैं या उन्हें बढ़ाया है। कास्टको, वालमार्ट और टारगेट जैसी कंपनियों ने तिमाही के दौरान मजबूत प्रदर्शन किया। आनलाइन बिक्री में तेजी और उपभोक्ताओं की लगातार खरीदारी ने इनके कारोबार को सहारा दिया। वहीं मैसीज़ और बेस्ट बाय जैसी कंपनियों में भी सुधार के संकेत मिले हैं। हालांकि कंपनियां अभी भी पूरी तरह निश्चिंत नहीं हैं। उन्हें चिंता है कि टैक्स रिफंड का फायदा धीरे-धीरे खत्म होगा, जबकि ऊंची ऊर्जा कीमतें और वैश्विक तनाव आगे कारोबार को प्रभावित कर सकते हैं। रिटेल कंपनियों की रणनीति में एक बड़ा बदलाव यह देखने को मिला है कि अब एआई सिर्फ प्रयोग या पायलट प्रोजेक्ट तक सीमित नहीं है। कंपनियां इसे सीधे अपने कारोबार में लागू कर रही हैं ताकि लागत कम हो, कर्मचारियों की उत्पादकता बढ़े और मुनाफा सुधरे। यानी एआई अब खर्च बढ़ाने वाली तकनीक नहीं, बल्कि कमाई बढ़ाने और मार्जिन सुधारने का जरिया बनता जा रहा है। यही बदलाव भारतीय आईटी कंपनियों के लिए चुनौती भी बन सकता है। अब कई ऐसे काम, जो पहले बड़ी आईटी टीमों के जरिए किए जाते थे, एआई की मदद से तेजी और कम लागत में पूरे हो रहे हैं। इसका असर खासकर एप्लिकेशन सपोर्ट, टेस्टिंग, क्वालिटी एश्योरेंस, रिपोर्टिंग और मेंटेनेंस जैसी सेवाओं पर पड़ सकता है। ये ऐसे क्षेत्र हैं जिनसे भारतीय आईटी कंपनियों को लंबे समय से बड़ा कारोबार मिलता रहा है। भारतीय आईटी कंपनियों के रिटेल और कंज्यूमर कारोबार में पिछले कुछ महीनों के दौरान सुधार देखने को मिला है।

न्यूज ब्रीफ

देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल कार वैगनआर लांच, चलेगी इथेनाल से

नई दिल्ली। कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने अपनी और देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल कार, वैगनआर को पेश कर दिया है। इस ऐतिहासिक लान्च को देश में साफ और ज्यादा विविध ईंधन विकल्पों को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जिसमें सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी उपस्थित थे। यह भारत की पहली पैसेंजर कार है जो ई20 से लेकर ई85 तक के इथेनाल-पेट्रोल मिश्रण पर चल सकती है, जिसमें शुद्ध 100 प्रतिशत इथेनाल (ई100) भी शामिल है। यह पहल केंद्र सरकार द्वारा इथेनाल-मिश्रित ईंधन के लिए नियामक ढांचे को व्यापक बनाने के ठीक बाद आई है। फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल (एफएफवी) वे वाहन होते हैं जिनमें एक इंटरनल कम्बशन इंजन होता है जो पेट्रोल और इथेनाल के अलग-अलग मिश्रणों पर चलने में सक्षम होता है। मारुति की यह नई वैगनआर ई100 पर भी आसानी से चलने के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई है। इसके लिए इंजीनियर्स ने इसके आंतरिक सिस्टम में व्यापक बदलाव किए हैं, जिसमें नए सिरे से डिजाइन किए गए इंजेक्टर, मजबूत फ्यूल लाइनें, टिकाऊ सील और एक खास तौर से कैलिब्रेटेड इंजन मैनेजमेंट सिस्टम शामिल है, ताकि यह इथेनाल की विशिष्ट रासायनिक विशेषताओं को बिना किसी दिक्कत के संभाल सके। यह कदम भारत के लिए कई आर्थिक और पर्यावरणीय लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करेगा। यह राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करता है, क्योंकि ईंधन स्थानीय कृषि उत्पादों जैसे गन्ने के शीरे, मक्का और कृषि कचरे से बनता है, जिससे विदेशी तेल पर निर्भरता कम होती है।

इनोवा क्रिस्टा का नया दमदार संस्करण लांच

नई दिल्ली। लोकप्रिय एमपीवी, इनोवा क्रिस्टा का नया संस्करण टोयोटा ने लान्च कर दिया है। नई टोयोटा इनोवा क्रिस्टा की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 19.72 लाख रुपये है, जो बेस जीएक्स 7-सीटर वेरिएंट के लिए है, और टाप जेडएक्स वेरिएंट की कीमत 26.63 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है। यह अपडेटेड माडल अपने एक्सटीरियर और इंटीरियर में कई बदलावों के साथ आता है, हालाँकि इसके इंजन और ट्रांसमिशन को पहले जैसा ही रखा गया है। नई इनोवा क्रिस्टा के फ्रंट में एक नया रेडिएटर ग्रिल और संशोधित फ्रंट व रियर बंपर गार्निश दिया गया है, जो इसके रोड प्रेजेंस को पहले से अधिक दमदार और शानदार बनाता है। केबिन के भीतर, ड्यूल-टोन लेदर सीट अपहोल्स्ट्री एक प्रीमियम एहसास देती है, जबकि इंस्ट्रूमेंट पैनल, डोर ट्रिम और बेजल्स पर ग्रेस कापर फिनिश को वुड-पैटर्न हाइलाइट्स के साथ जोड़ा गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए, चयनित वेरिएंट्स में वायरलेस चार्जर और टायर प्रेशर मानिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) जैसी आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। सुरक्षा के लिहाज से, नई इनोवा क्रिस्टा में 7 एयरबैग, एंटी-लाक ब्रेकिंग सिस्टम (एबीएस), व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल (वीएससी), हिल स्टार्ट असिस्ट और इलेक्ट्रानिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन (ईबीडी) जैसे फीचर्स दिए गए हैं, जो चालक और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।

आवश्यकता पड़ने पर स्वयं रफ्तार नियंत्रित कर सकेंगी यामाहा की बाइक

नई दिल्ली। दो पहिया वाहन निर्माता कंपनी यामाहा चालक की सुरक्षा और आराम को प्राथमिकता देते हुए उन्नत तकनीकों पर काम कर रही है। यामाहा ऐसी प्रणालियां विकसित कर रही है जो आवश्यकता पड़ने पर स्वयं रफ्तार नियंत्रित कर सकेंगी, स्वचालित रूप से ब्रेक लगा सकेंगी। इतना ही नहीं, इंजन की स्थिति के अनुसार गियर भी बदल सकेंगी। यह आने वाले वर्षों में मोटरसाइकिल चलाने के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है। वर्तमान में कई प्रीमियम मोटरसाइकिलों में रफ्तार नियंत्रण प्रणाली मौजूद है, जिससे लंबी यात्राओं में चालक को आराम मिलता है। यामाहा इस प्रणाली को और अधिक बुद्धिमान बनाने की दिशा में अग्रसर है, ताकि यह सड़क और यातायात की स्थिति के अनुरूप गति को स्वतः समायोजित कर सके। सुरक्षा के मोर्चे पर, स्वचालित ब्रेक प्रणाली एक महत्वपूर्ण नवाचार है। यह प्रणाली संवेदकों और कैमरों की मदद से सड़क पर बाधाओं को पहचानती है और टक्कर की संभावना होने पर स्वयं ब्रेक लगाती है, जिससे दुर्घटनाओं की गंभीरता कम होती है या उन्हें टाला जा सकता है।

बैंकिंग सेक्टर के लिए अलर्ट : नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर दबाव, दरें बढ़ीं तो बदल जाएगा सारा खेल

क्रेडिट ग्रोथ मजबूत, लेकिन पश्चिम एशिया संकट और महंगे तेल से बढ़ सकता है जोखिम

नई दिल्ली

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने जून की मौद्रिक नीति समीक्षा में लगातार स्थिरता का रुख अपनाते हुए रेपो रेट को 5.25 प्रतिशत पर बरकरार रखा है। साथ ही केंद्रीय बैंक ने अपनी न्यूट्रल पालिसी स्टांस को भी जारी रखा है, जिसे बाजार विशेषज्ञ फिलहाल वेट एंड वाच की रणनीति मान रहे हैं। इसका अर्थ है कि आरबीआई अभी अर्थव्यवस्था के घरेलू और वैश्विक संकेतकों पर नजर रखते हुए किसी बड़े नीतिगत बदलाव से बच रहा है। नीति घोषणा के बाद बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के शेयरों में हल्की तेजी देखने को मिली, लेकिन बाजार में व्यापक अनिश्चितता बनी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि महंगा कच्चा तेल, कमजोर मानसून की आशंका और रुपये पर दबाव जैसे कारक आने वाले महीनों में मुद्रास्फीति को प्रभावित कर सकते हैं। यदि ये परिस्थितियां बनी रहती हैं तो ब्याज दरों के मौजूदा चक्र में बदलाव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, और दरों में बढ़ोतरी का दौर दोबारा शुरू हो सकता है।

आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मौद्रिक नीति की घोषणा के दौरान कहा कि वैश्विक आर्थिक वातावरण अप्रैल की पिछली बैठक के बाद और अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है। विशेष रूप से पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव ने वैश्विक सप्लाई चेन को प्रभावित किया है, जिससे तेल और गैस की कीमतों में तेजी आई है। इसका सीधा असर वैश्विक विकास दर पर पड़ने के साथ-साथ महंगाई के दबाव को भी बढ़ा रहा है। केंद्रीय बैंक ने वित्त वर्ष 2027 के लिए खुदरा महंगाई दर (सीपीआई) का अनुमान बढ़ाकर 5.1 प्रतिशत कर दिया है, जो पहले 4.6 प्रतिशत के आसपास था। वहीं, आर्थिक विकास के मोर्चे पर जीडीपी ग्रोथ अनुमान को 6.9 प्रतिशत से घटाकर 6.6 प्रतिशत कर दिया गया है। यह संशोधन दर्शाता है कि आरबीआई आने वाले समय में धीमी लेकिन स्थिर विकास दर की संभावना देख रहा है, जबकि महंगाई एक चुनौती बनी रह सकती है। बैंकिंग सेक्टर पर इस नीति का मिला-जुला प्रभाव देखने को मिल रहा है। एक्सिस सिक्योरिटीज पीएमएस के एक अधिकारी के अनुसार मार्च तिमाही में बैंकों का प्रदर्शन मजबूत रहा है। क्रेडिट ग्रोथ लगभग 16 प्रतिशत के स्तर पर बनी हुई है और एसेट क्वालिटी में भी सुधार देखा गया है। हालांकि, आगे चलकर भू-राजनीतिक तनाव लंबे समय तक जारी रहा तो इसका असर एमएसएमई, वाहन वित्त और तेल-संवेदनशील कारपोरेट सेक्टरों पर दिख सकता है। इसके अलावा बैंकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती नेट इंटरेस्ट मार्जिन (एनआईएम) को लेकर है। जमा जुटाने की प्रतिस्पर्धा बढ़ने और फंड की लागत ऊंची रहने से मार्जिन पर दबाव बना रह सकता है। स्टाक मार्केट में भी इस नीति का असर साफ दिखाई दिया। बैंकिंग और एनबीएफसी शेयरों में हल्की तेजी रही। एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जैसे शेयरों में मजबूती देखी गई, जबकि एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक में कुछ गिरावट दर्ज की गई। विशेषज्ञ निवेश रणनीति में चयनात्मक दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दे रहे हैं। उनकी पसंद में आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और एसबीआई जैसे बड़े बैंक शामिल हैं, जबकि मिड और स्माल बैंकिंग स्पेस में फेडरल बैंक और उज्जीवन स्माल बैंक को प्राथमिकता दी जा रही है। एनबीएफसी सेक्टर में बजाज फाइनेंस को मजबूत विकल्प माना जा रहा है। कुल मिलाकर आरबीआई की यह नीति संकेत देती है कि फिलहाल स्थिरता प्राथमिकता है, लेकिन वैश्विक जोखिम और घरेलू महंगाई आने वाले समय में मौद्रिक नीति की दिशा बदल सकते हैं।

ओवरटाइम पर अब सख्ती: काम भी डबल, भुगतान भी डबल

नई दिल्ली

नए लेबर कोड्स से बदले नियम, कर्मचारियों को मिला कानूनी और आर्थिक सुरक्षा कवच

देश की फैक्ट्रियों, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और कारपोरेट दफ्तरों में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों के लिए ओवरटाइम हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। अक्सर काम के बढ़ते दबाव, प्रोजेक्ट डेडलाइन या पीक सीजन के नाम पर कर्मचारियों से तय समय से अधिक काम कराया जाता है, लेकिन इसके बदले मिलने वाला उचित भुगतान कई बार विवाद का कारण बनता है।

कई मामलों में कर्मचारियों को या तो बहुत कम अतिरिक्त भुगतान दिया जाता है या फिर ओवरटाइम के पैसे को लेकर कंपनियों की ओर से टालमटोल की स्थिति देखने को मिलती है। हालांकि, सरकार द्वारा लागू किए गए नए लेबर कोड्स ने इस पूरी व्यवस्था में बड़ा और सख्त बदलाव किया है। विशेषज्ञों के अनुसार कोड आन वेजेस, 2019 के तहत यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि कोई कर्मचारी अपने निर्धारित कार्य घंटों से अधिक काम करता है, तो उसे उसके सामान्य वेतन की दोगुनी दर से ओवरटाइम का भुगतान करना अनिवार्य होगा। इस प्रावधान का उद्देश्य कर्मचारियों को उनके अतिरिक्त श्रम का उचित और न्यायसंगत मुआवजा दिलाना है, जिससे लंबे समय से चली आ रही असमानता को दूर किया जा सके।

इसके साथ ही आक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड, 2020 (ओएसएच कोड) में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस कोड के तहत अब किसी भी कर्मचारी से ओवरटाइम कराने से पहले उसकी स्पष्ट सहमति लेना कानूनी रूप से अनिवार्य होगा। यानी अब कंपनियां कर्मचारियों पर अतिरिक्त काम के लिए दबाव नहीं बना सकेंगी और बिना अनुमति के ओवरटाइम नहीं कराया जा सकेगा। यह नया कानूनी ढांचा पुराने फैक्ट्री एक्ट, माइंस एक्ट और अन्य श्रम कानूनों को एकीकृत करता है। इसके दायरे में अब ग्रेनाइट प्रोसेसिंग यूनिट्स, खनन क्षेत्र, फैब्रिकेशन यार्ड्स और अन्य सभी छोटे-बड़े उद्योग शामिल हो गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इन नए नियमों से न केवल कर्मचारियों के अधिकार मजबूत होंगे, बल्कि कंपनियों की उस परंपरागत कार्य संस्कृति पर भी रोक लगेगी, जिसमें ओवरटाइम को सस्ते श्रम के रूप में देखा जाता था। इससे आने वाले समय में कार्यस्थल पर पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों बढ़ने की उम्मीद है।

नई पीढ़ी की हाइब्रिड सुपरकार टेमेरारियो की डिलीवरी शुरु

नई दिल्ली। इटली की प्रतिष्ठित सुपरकार निर्माता लेम्बोर्गिनी ने अपनी नई पीढ़ी की हाइब्रिड सुपरकार टेमेरारियो की पहली डिलीवरी के साथ एक नया अध्याय शुरू कर दिया है। सुपरकार टेमेरारियो लगभग 5.87 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उपलब्ध है। यह लेम्बोर्गिनी की विद्युतीकरण यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो हुराकान की जगह लेगी। टेमेरारियो अत्याधुनिक तकनीक, जबरदस्त प्रदर्शन और भविष्य की मोटरिंग अवधारणा का बेहतरीन उदाहरण मानी जा रही है। लेम्बोर्गिनी टेमेरारियो के केंद्र में पूरी तरह नया 4.0 लीटर ट्विन-टर्बो वी8 इंजन है, जिसके साथ तीन विद्युत मोटर और एक 3.8 किलोवाट-घंटा क्षमता का बैटरी पैक जोड़ा गया है। यह संयुक्त रूप से 907 बीएचपी की शक्ति और 800 न्यूटन मीटर का टार्क पैदा करता है। केवल वी8 इंजन ही 789 बीएचपी की शक्ति उत्पन्न करता है और 10,000 आरपीएम तक घूम सकता है। यह शक्ति आठ-स्पीड डुअल-क्लच स्वचालित गियरबाक्स के माध्यम से चारों पहियों तक पहुँचती है। प्रदर्शन के मामले में, यह सुपरकार महज 2.7 सेकंड में स्थिर अवस्था से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल कर सकती है और इसकी अधिकतम गति 343 किलोमीटर प्रति घंटा बताई गई है।

8 महीने में आधे से ज्यादा टूट गया बिटकॉइन, 60 हजार डॉलर से नीचे फिसला; निवेशकों का भरोसा डगमगाया

नई दिल्ली

दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन में गिरावट का सिलसिला जारी है। शनिवार को बिटकॉइन अक्टूबर 2024 के बाद पहली बार 60,000 डॉलर के महत्वपूर्ण स्तर से नीचे पहुंच गया। सुबह के कारोबार में इसमें करीब 7 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई और इसकी कीमत 59,101 डॉलर तक फिसल गई। बाद में इसमें कुछ सुधार देखने को मिला और यह 59,743 डॉलर के आसपास कारोबार करता रहा।

बिटकॉइन की मौजूदा गिरावट इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि यह अक्टूबर 2025 में बने अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर 1.26 लाख डॉलर से अब आधे से भी कम रह गया है। पिछले आठ महीनों में निवेशकों की संपत्ति में भारी कमी आई है और बाजार में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है।

विशेषज्ञों के अनुसार क्रिप्टोकरेंसी बाजार पर दबाव का सबसे बड़ा कारण निवेशकों की बदलती प्राथमिकताएं हैं। हाल के महीनों में बड़ी संस्थागत पूंजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), रक्षा, ऊर्जा और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों की ओर शिफ्ट हुई है। इसके चलते क्रिप्टो बाजार से लगातार धन निकासी देखी जा रही है। इसके अलावा सोने और एआई आधारित कंपनियों के शेयरों में बढ़ती रुचि ने भी बिटकॉइन जैसे डिजिटल एसेट्स की मांग को प्रभावित किया है।

अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दर नीति को लेकर बदले हुए अनुमान भी बाजार की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। निवेशकों का मानना है कि उच्च ब्याज दरों का माहौल जोखिम वाले निवेश विकल्पों पर दबाव बढ़ाता है, जिसका असर क्रिप्टोकरेंसी पर भी दिखाई दे रहा है।

बाजार विश्लेषकों की नजर अब 60,000 से 62,000 डॉलर के दायरे पर टिकी हुई है, जिसे बिटकॉइन के लिए महत्वपूर्ण समर्थन स्तर माना जा रहा है। यदि यह स्तर बरकरार रहता है तो निवेशकों का भरोसा लौट सकता है, लेकिन इसके नीचे लगातार कारोबार होने पर गिरावट और गहरी हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले समय में एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में निवेश प्रवाह, संस्थागत भागीदारी, वैश्विक आर्थिक हालात और भू-राजनीतिक घटनाक्रम बिटकॉइन की दिशा तय करेंगे।

हफ्तेभर बाजार में हाहाकार, सेंसेक्स-निफ्टी की चाल ने बढ़ाई निवेशकों की धड़कनें

वैश्विक तनाव, एफआईआई बिकवाली और आरबीआई के फैसलों के बीच शेयर बाजार में जबरदस्त उठापटक

मुंबई

घरेलू शेयर बाजार के लिए बीता सप्ताह बेहद अस्थिर और चुनौतीपूर्ण रहा। सप्ताहभर सेंसेक्स और निफ्टी में तेज उतार-चढ़ाव देखने को मिला। कभी खरीदारी ने बाजार को संभाला तो कभी वैश्विक चिंताओं और विदेशी निवेशकों की बिकवाली ने निवेशकों का मूड बिगाड़ दिया। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, अमेरिका-ईरान वार्ता को लेकर अनिश्चितता और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक ने बाजार की दिशा पर गहरा असर डाला। सप्ताह की शुरुआत सकारात्मक रही।

सोमवार को सेंसेक्स 74,981 अंक तक पहुंच गया था और निफ्टी 23,600 के पार निकल गया था। लेकिन यह तेजी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। कारोबार के दौरान भारी मुनाफावसूली देखने को मिली और सेंसेक्स 508 अंकों की गिरावट के साथ 74,267 अंक पर बंद हुआ। दिनभर में 1,164 अंकों का उतार-चढ़ाव निवेशकों की बेचैनी को दर्शाता रहा। मंगलवार को बाजार ने मजबूत वापसी की। शुरुआती दबाव के बावजूद निचले स्तरों पर खरीदारी बढ़ी और सेंसेक्स 382 अंकों की छलांग लगाकर 74,649 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी भी 23,483 अंक तक पहुंचने में सफल रहा। आईटी और चुनिंदा बड़े शेयरों में खरीदारी ने बाजार को सहारा दिया। हालांकि बुधवार को फिर माहौल बदल गया। अमेरिका-ईरान वार्ता को लेकर बढ़ी अनिश्चितता और कमजोर वैश्विक संकेतों ने बाजार पर दबाव बनाया। सेंसेक्स कारोबार के दौरान 700 अंकों से अधिक टूट गया और अंततः 304 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ। गुरुवार को भी बाजार में भारी अस्थिरता रही। सेंसेक्स 74,544 के उच्च स्तर और 73,807 के निचले स्तर के बीच झूलता रहा। अंत में यह मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन निवेशकों की नजर आरबीआई की मौद्रिक नीति पर रही। शुरुआती तेजी के बावजूद बाजार में मुनाफावसूली हावी हो गई और सेंसेक्स 116 अंक गिरकर 74,243.34 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 23,366.70 के स्तर पर आ गया। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले सप्ताह में वैश्विक भू-राजनीतिक घटनाक्रम, विदेशी संस्थागत निवेशकों की गतिविधियां और ब्याज दरों से जुड़े संकेत बाजार की चाल तय करेंगे। फिलहाल निवेशकों को सतर्क रहकर गुणवत्ता वाले शेयरों पर फोकस करने की सलाह दी जा रही है।